श्री योगी आदित्यनाथ

मा. मुख्यमंत्री

स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश
(एस०यू०डी०एम०-यू०पी०)

बुकलेट का विमोचन
06 अप्रैल, 2023

श्री राकेश राठौर 'गुरु'
राज्य मंत्री

श्री ए. के. शर्मा
मंत्री

नगर विकास, नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में नगरों का सर्वाधिक योगदान होता है। विगत कुछ वर्षों में देश एवं प्रदेश में नगरीकरण की प्रवृत्ति एवं ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं का डिजिटाइजेशन तेजी से बढ़ा है। जन-आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जन-सामान्य को आवश्यक मूल-भूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जन उपयोगी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का शुभारंभ किया गया है।

हमारे नगर अर्थ-व्यवस्था के ग्रोथ-इंजन के रूप में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत-वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या के साथ ही सर्वाधिक नगरीय निकायों वाला प्रदेश है। प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगरीय निकायों का सीमा-विस्तार/गठित/उच्चीकरण किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 762 नगरीय निकाय हैं, जिसमें 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं।

नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति एवं राज्य भर में शहरी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु नगरीय सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने, प्रदेश में डिजिटल तकनीक को प्रोत्साहन, सुदृढ़ अर्बन डिजिटल ढांचा तैयार करना, अर्बन उत्तर प्रदेश को सशक्त करना, , राज्य के समस्त निकायों में सुलभ समावेशी, कुशल और नागरिक केन्द्रिय ऑनलाइन सेवाओं को "सरकार आपके द्वार पर" की अवधारणा के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य दिनांक 31.05.2022 को एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया। जिसके अंतर्गत आवास एवं शहरी मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की एंकरिंग संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर मानकों तथा यूनिक विशिष्टताओं पर तैयार डिजिटल प्लैटफ़ार्म, अर्बन प्लैटफ़ार्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेन्स (UPYOG) प्रदान करने में सतत सहयोग उपलब्ध कराया जाना है।

प्रदेश में म्यूनिसिपल सेवाओं को ऑनलाइन 24 X 7 नागरिकों को उपलब्ध कराने एवं राष्ट्रीय मानकों के समरूप डिजिटल प्लेटफार्म को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से नगर विकास विभाग के अधीनस्थ प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकायों में समुचित, सक्षम, उपयुक्त एवं प्रभावी नागरिक केन्द्रित सुविधाएं प्रदान कर प्रदेश को डिजिटली सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश (SUDM-UP) का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है।

विषय सूची

1. संदर्भ.....4-7
2. एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के उद्देश्य.....8-10
3. एस०यू०डी०एम०-यू०पी० की राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति.....11
4. एस०यू०डी०एम०-यू०पी० की प्रबन्ध समिति.....11
5. एस०यू०डी०एम०-यू०पी० का डैशबोर्ड.....12-13
6. एस०यू०डी०एम०-यू०पी० का वित्तीय प्रावधान.....14
7. एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के स्टेकहोल्डर्स के लिए लाभ.....15-16
8. एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के सिद्धांत.....16
9. एस०यू०डी०एम०-यू०पी० का रोल-आउट.....17

संदर्भ

सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार के पत्र सं०- K-14012/101(01)/2019-SC-Desk-(IV) दिनांक: 13.09.2021 के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के उपलक्ष में MoHUA द्वारा देश के प्रत्येक कस्वों एवं शहरों में म्युनिसिपल सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन प्रारम्भ किया गया है। इस मिशन के रोल-आउट के लिए MoHUA द्वारा एंकरिंग संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एन०आई०यू०ए०) को चयनित किया गया है।

उपरोक्त पत्र के क्रम में संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार के पत्र सं०- K-14012/101(01)/2012-SC-Desk-(IV) दिनांक: 10.05.2022 में MoHUA द्वारा विभिन्न राज्यो एवं केंद्र शासित प्रदेशों में म्युनिसिपल सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आधार ऑफरिंग के रूप में रेफरेंस अर्बन प्लैटफ़ार्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेन्स (UPYOG) विकसित किया गया है जो कि राज्य सरकारों को यह विकल्प देता है कि वो उपयोग (UPYOG) प्लैटफ़ार्म को या तो सर्विस मॉडल या राज्य होस्टेड मॉडल या पूर्व में राज्य में कार्यरत प्लैटफ़ार्म और कुछ मानकों के साथ डाटा एग्रीगेटिड रिपोर्टिंग के आधार पर प्रयोग में लिया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी अनुरोध किया गया कि राज्य में ऑनलाइन डिजिटल मोड पर नागरिक सेवाओं को प्रदान करने एवं राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिसिस को रिप्लीकेट करने के उद्देश्य से एक त्रि-पक्षीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एम०ओ०यू०) MoHUA, भारत सरकार, एंकरिंग संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एन०आई०यू०ए०) एवं नगर विकास विभाग, राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना उचित रहेगा।

उक्त के क्रम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य दिनांक 31.05.2022 को एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया। जिसके अंतर्गत आवास एवं शहरी मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार के नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की एंकरिंग संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर मानकों तथा यूनिक विशिष्टताओं पर तैयार डिजिटल प्लैटफ़ार्म, अर्बन प्लैटफ़ार्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेन्स (UPYOG) प्रदान करने में सतत सहयोग उपलब्ध कराया जाना है।

प्रदेश में ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में समस्त नगरीय निकायों को सहयोग देने हेतु स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एस०यू०डी०एम०-यू०पी०) को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत सोसायटी गठित कर प्रारम्भ किया गया है।

दुर्गा शंकर मिश्र
सचिव
Durga Shanker Mishra
Secretary

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

K-14012/101(01)/2019-SC-Desk-(IV)
September 13, 2021

Dear Chief Secretary,

At the outset, I commend your efforts towards promoting e-governance solutions in your State/ UT. The implementation of online services for citizens benefits, holds a valuable lesson for the nation.

2. As we celebrate *Azadi ka Amrit Mahotsav* marking the 75th year of our country's independence, MoHUA has launched the National Urban Digital Mission (NUDM) to facilitate electronic delivery of municipal services to citizens across all towns and cities of the country. The Ministry looks forward to partnering and complementing in the significant efforts already made by you in this regard.

3. The rollout of Online Building Permission Systems (OBPS) has led to significant improvement of India's performance in World Bank's Ease of Doing Business Index. Moreover, a diverse range of e-governance solutions have been deployed in many States and cities, contributing to ease of living for India's urban residents. However, in order to achieve scale and speed in implementing such solutions in a systemic, integrated and sustainable manner, lot more efforts are needed. NUDM has been conceived in this background. It targets rollout of a bouquet of electronic e-governance solutions in 2022 towns and cities by 2022 and in all of them by 2025.

4. The open-source National Urban Governance Platform created to facilitate this journey will host key urban services such as: water and sewerage, birth and death registration, citizens' grievance redressal, online building permits, NOC, property tax, trade license, municipal accounting, and miscellaneous user fees. Along with this platform, the Mission will also make available empanelled and trained implementation partners, tools, templates, technical assistance to facilitate ease of roll out. At the core of Mission design is the choice-architecture built in the Technical Implementation Guidelines to enable States to drive the implementation as per their preferred modes. The Centre for Digital Governance at NIUA is working on behalf of the Ministry to roll out the Mission. You may reach out to Ms. Kakul Misra at cdg-contact@niua.org for any queries.

Contd..2/-

Office Address: Room No. 122 'C' Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Tel.: 011-23062377, 23061179; Fax: 011-23061459; Email: secyurban@nic.in
Website: www.mohua.gov.in

5. I request you to provide strong leadership to NUDM in your State. Our team at CDG, NIUA will reach out to present Mission details to you and your team; and understand how they can support your vision and plans for urban e-governance rollout in your State. I also request you to appoint a Nodal Officer at the earliest and inform at the email id above to facilitate our partnership going forward.

Regards,

Yours Sincerely,

(Durga Shanker Mishra)

Chief Secretaries of all States/ UTs.

कुणाल कुमार, भा.प्र.से.
KUNAL KUMAR, IAS
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक
स्मार्ट सिटिज मिशन
Joint Secretary & Mission Director
Smart Cities Mission

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING & URBAN AFFAIRS

K-14012/101(01)/2022-SC-Desk- (IV)

Date 10th May, 2022

Dear Sir, Ma'am, colleagues,

Please refer to D.O letter of even no. dated 13th September, 2021 from Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) regarding the implementation of online services under NUDM.

2. The National Urban Digital Mission (NUDM) is one of the key initiatives of MoHUA, with the objective of leveraging IT for improving transparency, governance, ease of doing business and capacity building. NUDM aims to support States and Union Territories (UTs) in the electronic delivery of municipal services, and supplement the digital initiatives of the State/UT Governments. MoHUA intends to enhance the ease of living for urban citizens by enabling accessibility of municipal services to citizens across all cities by 2025.

3. MoHUA has developed a national reference platform for municipal services named **Urban Platform for deliverY of Online Governance (UPYOG)** as a key offering under NUDM to every State and UT. UPYOG is an open-source, shared digital platform to enable the rollout of municipal e-Governance services. It includes nine reference modules for most commonly used urban services including grievance redressal, online building plan approval and property tax among others. The state-wise dashboard on UPYOG will display an integrated view of services at the State/ UT level such as the number of properties in State/ UT or ULBs, the total demand of property tax, the percentage of tax collected, and other key performance indicators. UPYOG will support towards data-driven governance, streamlining workflows and processes.

4. NUDM has a flexible approach wherein States/UTs have the option to adopt UPYOG based on their maturity and needs- either on a Platform as a Service model; or State hosted model; or continue with their systems and only use standards for data aggregated reporting.

5. I encourage all States/UT's to take advantage of NUDM for their cities and ensure that citizens are provided with the best possible services through online/ digital mode and that the best practices are replicated across the country. To initiate the process, I request you to peruse and sign the **tripartite Memorandum of Understanding** between MoHUA, NIUA and the designated State/UT Authority nominated to anchor the implementation of NUDM in your State/UT (enclosed as Annexure-1).

6. Additionally, I request you to kindly appoint a Nodal Officer to facilitate this engagement and the details may be sent to cdg-contact@niua.org. You may reach out to Ms. Kakul Misra, Head, Centre for Digital Governance and/or Shri Manpreet Singh, Chief Program Officer at NIUA, at cdg-contact@niua.org for any queries.

With regards.

Yours sincerely,

(Kunal Kumar)

Encl.: As stated above

To,
Principal Secretaries (UD) of all State/ UTs.

Office Address: Room No. 138-C, Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Tel.: 011-23063255, 23062028; Email: krkunal@ias.nic.in; Website: www.mohua.gov.in

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के उद्देश्य

स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश (एस०यू०डी०एम०-यू०पी०) के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है: -

(1) एस०यू०डी०एम०-यू०पी० द्वारा उत्तर प्रदेश में एन०यू०डी०एम० के प्रारम्भिक क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की योजना बनायी जाएगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के समकुल शहरी सर्वोत्तम सेवाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा और क्रॉस / अंतर-डोमेन शिक्षा, नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा देगा।

(2) एस०यू०डी०एम०-यू०पी० नगरीय क्षेत्र में विभिन्न मिशनों/परियोजनाओं के लिए लक्ष्य प्राप्ति और मॉनिटरिंग की सुविधा प्रदान करेगा। एस०यू०डी०एम०-यू०पी० नगर विकास विभाग के अधीन विभिन्न संस्थानों के लिए एक नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा एवं ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों के लिए एक आत्मनिर्भर राजस्व सृजन तंत्र विकसित करने पर सकारात्मक सहयोग प्रदान करेगा।

(3) उत्तर प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों और पैरास्टेटल संस्थाओं को एक व्यवसायिक सूचना प्रौद्योगिकी / ई-गवर्नेंस वातावरण प्रदान करना।

(4) निकायों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑनलाइन गवर्नमेंट टू सिटीज़न (G2C), गवर्नमेंट टू बिज़नस (G2B) और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट (G2G) सेवाओं की सुविधा देकर एक व्यवसायिक शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए **ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था** में सहयोग करना।

(5) ईज ऑफ लिविंग (EoL) के अन्तर्गत आई०टी०, आई०टी०ई०एस० एवं अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हुये नागरिक केन्द्रित सुविधाओं को सुदृढ़ करना, उपलब्ध कराना एवं उनका प्रभावी क्रियान्वयन कराना।

(6) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) को बढ़ावा देते हुए इन क्षेत्रों में आधुनिक डिजिटल तकनीकों का प्रयोग कर आवश्यक अनापत्तियां आदि निर्धारित समयान्तर्गत निर्गत कराना। डिजिटल तकनीक के उपयोग के कारण कार्यों में पारदर्शिता, त्वरित निस्तारण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित होने के फलस्वरूप नगरीय निकायों की आय में सम्भावित वृद्धि के दृष्टिगत शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ करते हुये ट्रिलियन डालर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।

(7) प्रदेश के निकायों में वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन सुनिश्चित कराना, पत्रावलियों के संचरण के लिये आवश्यक प्रणाली विकसित कराना, मानव सम्पदा एवं परिसम्पत्तियों के लिये प्रबन्धन प्रणाली विकसित कराना एवं अन्य आवश्यक जी-टू-जी (G2G) सेवाओं का विकास, प्रबन्धन एवं संचालन सुनिश्चित कराना।

(8) डिजिटल तकनीकों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं, अनापत्तियों और उनके नियमित अनुश्रवण तथा प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप नगरीय निकायों के राजस्व स्रोतों में वृद्धि कराना।

(9) प्रदेश/अन्य प्रदेशों में संचालित विभिन्न योजनाओं/मिशन्स के अनुभवों, बेस्ट प्रैक्टिसेज का डिजिटल तकनीकों के माध्यम से अभिलेखीकरण एवं उन्हें अन्य निकायों के साथ साझा करते हुये उनका लाभ उपलब्ध कराना, इस प्रकार प्रयास की द्विरावृत्ति को समाप्त कर धन एवं समय की बचत सुनिश्चित करना।

(10) समस्त नगरीय निकायों में म्युनिसिपल सेवाओं को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए AMRUT 2.0 के रिफॉर्म एजेंडा के अंतर्गत ऑनलाइन म्युनिसिपल सेवा प्रणाली को विकसित किया जाना।

(11) उपयोग (UPYOG) प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए आवश्यक रोल-आउट प्लान सुनिश्चित कराना तथा अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग और उन्हें निर्धारित नियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार परिवर्तित/परिवर्धित करना एवं उपयोग (UPYOG) प्लेटफार्म पर उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग करते हुए नवाचार सुनिश्चित कराना।

(12) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के साथ आवश्यकतानुसार मानकीकृत डेटा शेयरिंग सुनिश्चित करना।

(13) राज्य स्तर पर क्लाउड आधारित अर्बन डाटा रिपोजिटरी की स्थापना करना, जिसके माध्यम से नगरीय निकायों की अर्बन इंवैंट्री तैयार करना, जिसमें नगरीय निकायों की सेवाओं, डेटा, सम्पत्तियों आदि का विवरण संरक्षित रखा जायेगा।

(14) निकायों को एस०यू०डी०एम०-यू०पी० स्तर पर तैयार किए गए एकीकृत साफ्टवेयर प्रयोग में तकनीकी सहायता प्रदान करना, आई०टी०/ई- गवर्नेन्स संबन्धित परियोजनाओं का अनुश्रवण करना, ट्रेनिंग एवं हैण्डहोल्डिंग करना, कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से मानव संसाधन विकास सुनिश्चित कराना तथा वित्तीय संसाधनों के चिन्हीकरण में सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय संस्थाओं एवं प्रदेश सरकार के मध्य सहयोग व समन्वय सुनिश्चित कराना।

(15) निकायों में ई-गवर्नेन्स का प्रयोग करते हुए अनुश्रवण, मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना तथा ट्रेनिंग, वर्कशाप आदि का आवश्यकतानुसार समय-समय पर आयोजन सुनिश्चित कराना।

(16) ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के लिए नगर विकास विभाग के अधीनस्थ नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। नगर विकास विभाग के अर्न्तगत नगरीय निकाय निदेशालय एवं समस्त मिशन्स आदि में डिजिटल तकनीकी के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करते हुए ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा देना।

(17) एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के संचालन गतिविधियों के संबंध में सर्वर, कंप्यूटर उपकरण एवं अन्य आवश्यक तकनीकी संसाधन, आवश्यक तकनीकी सेवाएं पी०एम०यू० गठित करते हुए, सिस्टम और एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर तथा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु आवश्यक अन्य संसाधन क्रय करना अथवा किराए पर लेना।

(18) विभिन्न पैरास्टेटल एजेन्सीज यथा उ०प्र० जल निगम (नगरीय), राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण (SUDA) आदि के माध्यम से अर्बन डिजिटल प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन सुनिश्चित कराना।

(19) नवीन तकनीकी पर आधारित डैशबोर्ड तैयार करना।

(20) स्टेट डैशबोर्ड पर राष्ट्रीय मेटा-डाटा मानकों के अनुरूप डाटा प्रदर्शित किया जाना ताकि नेशनल डैशबोर्ड के अनुसार डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट एवं डाटा ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके।

(21) कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत निकाय स्तर पर कार्यरत कर्मियों को कैडर आधारित सर्टिफाइड ट्रेनिंग उपलब्ध कराना।

(22) पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राइट ऑफ वे (RoW) योजना, भू-स्थानिक तकनीकी अनुप्रयोग, सुगम के माध्यम से बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदाताओं को अनुमति प्रदान करने के लिए निकायों की सहायता करना।

(23) निकायों के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ राज्यव्यापी स्केलेबल एप्लिकेशन सिस्टम के साथ विकास और इंटरफेस को बढ़ावा देना।

(24) कर निर्धारण और संग्रह (संपत्ति, पानी, सीवरेज, आदि) के साथ-साथ गैर-कर राजस्व वृद्धि सहित अपने स्वयं के राजस्व जुटाने में सुधार करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करना।

(25) सुविधाजनक, आसान, किफायती, त्वरित और सुरक्षित तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी शहरी नागरिकों को निर्बाध डिजिटल भुगतान विकल्प की सुविधा प्रदान करना।

(26) ई-गवर्नेंस की संभावनाओं का उपयोग करते हुए शहरी स्थानीय निकायों की सभी गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना, जिससे उनके कार्यों में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक लंबी छलांग लगाई जा सके।

(27) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की सुविधा प्रदान करना और पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों को प्रकाशित करना, सेमिनार, संगोष्ठी, समर्थन सत्र आदि आयोजित करना।

(28) विभिन्न शीर्ष संस्थाओं/अन्य राज्यों से भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एम०ओ०यू० आदि करना।

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० की राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के नियमों और विनियमों एवं अन्य निर्णय संबन्धित प्रबंधन का कार्य राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता पदेन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जानी है। उक्त समिति के उपाध्यक्ष पदेन अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग एवं सदस्य सचिव पदेन मिशन निदेशक, एस०यू०डी०एम०-यू०पी० / पदेन निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय होंगे। राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के अन्य पदेन सदस्य क्रमशः अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), राज्य मिशन निदेशक, अमृत, राज्य मिशन निदेशक, एस०बी०एम० हैं।

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० की प्रबन्ध समिति

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के प्रबंधन, तकनीकी एवं वित्तीय प्रबन्ध आदि कार्य प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता पदेन अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा की जानी है। उक्त समिति के उपाध्यक्ष पदेन राज्य मिशन निदेशक, अमृत एवं सदस्य सचिव / मिशन निदेशक, एस०यू०डी०एम०-यू०पी० पदेन निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय होंगे। प्रबन्ध समिति के अन्य पदेन सदस्य क्रमशः प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), राज्य मिशन निदेशक, एस०बी०एम०, निदेशक, सूडा, निदेशक, नगरीय परिवहन मिशन, सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, एन०आई०यू०ए०-MoHUA द्वारा अर्बन एवं आई०टी० डोमेन में दक्ष नामित सदस्य, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति / संयोजक द्वारा नामित सदस्य, टीम लीडर, राज्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित), समन्वयक (आई०टी०), नगर विकास विभाग (प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित), आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० का डैशबोर्ड

अर्बन रियल-टाइम डैशबोर्ड ऑनलाइन सेवा वितरण के चैनल से जुड़े और इससे लाभान्वित होने वाले नागरिकों की कुल संख्या को दर्शाएगा। यह नगरीय सेवाओं के लिए कुल संग्रह, लक्ष्य उपलब्धि, कुल आवेदन और सेवा स्तर की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित करेगा।

- **कार्यरत ई-नगरसेवा रियल-टाइम डैशबोर्ड**

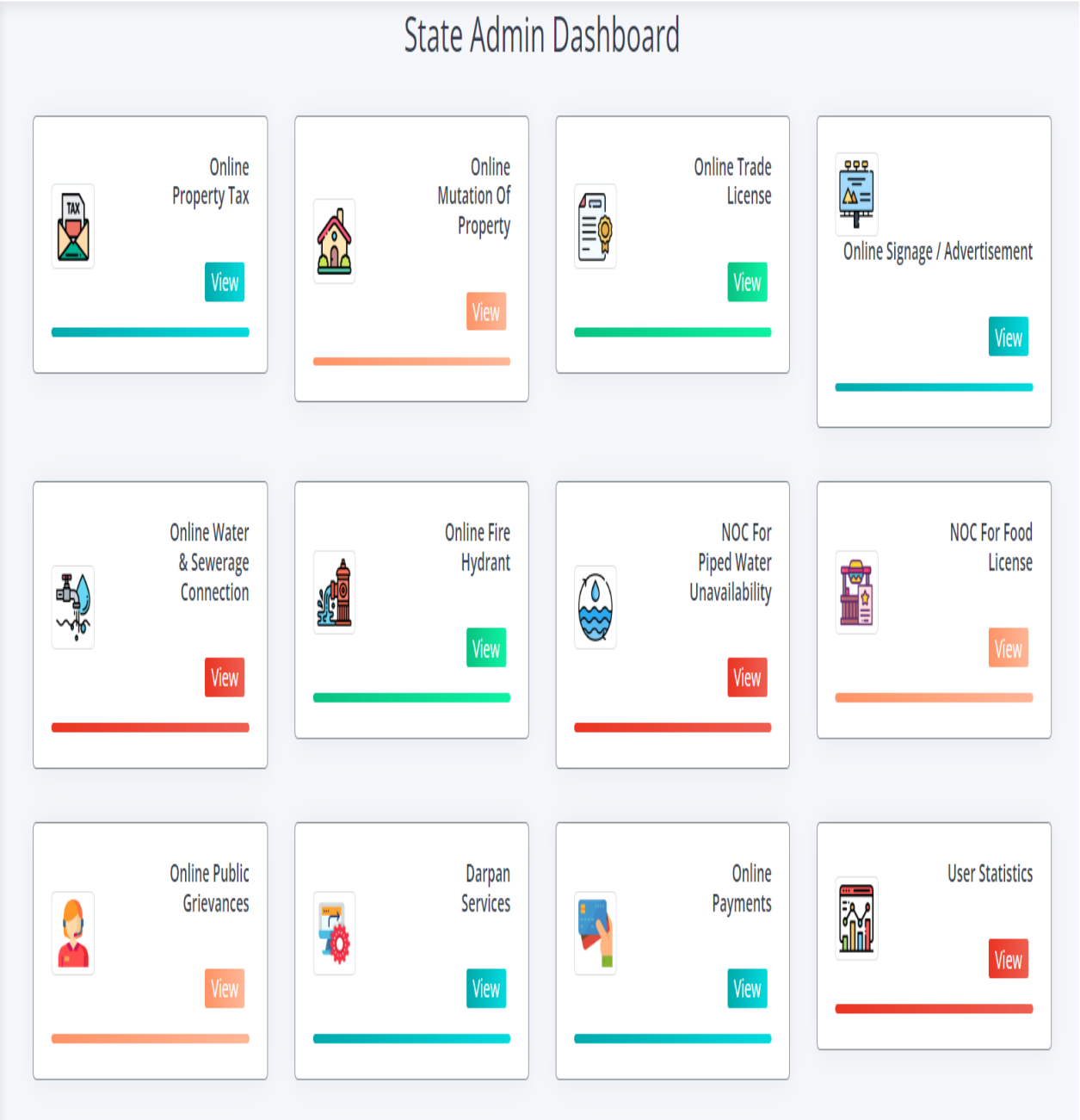

➢ नेशनल अर्बन रियल-टाइम डैशबोर्ड

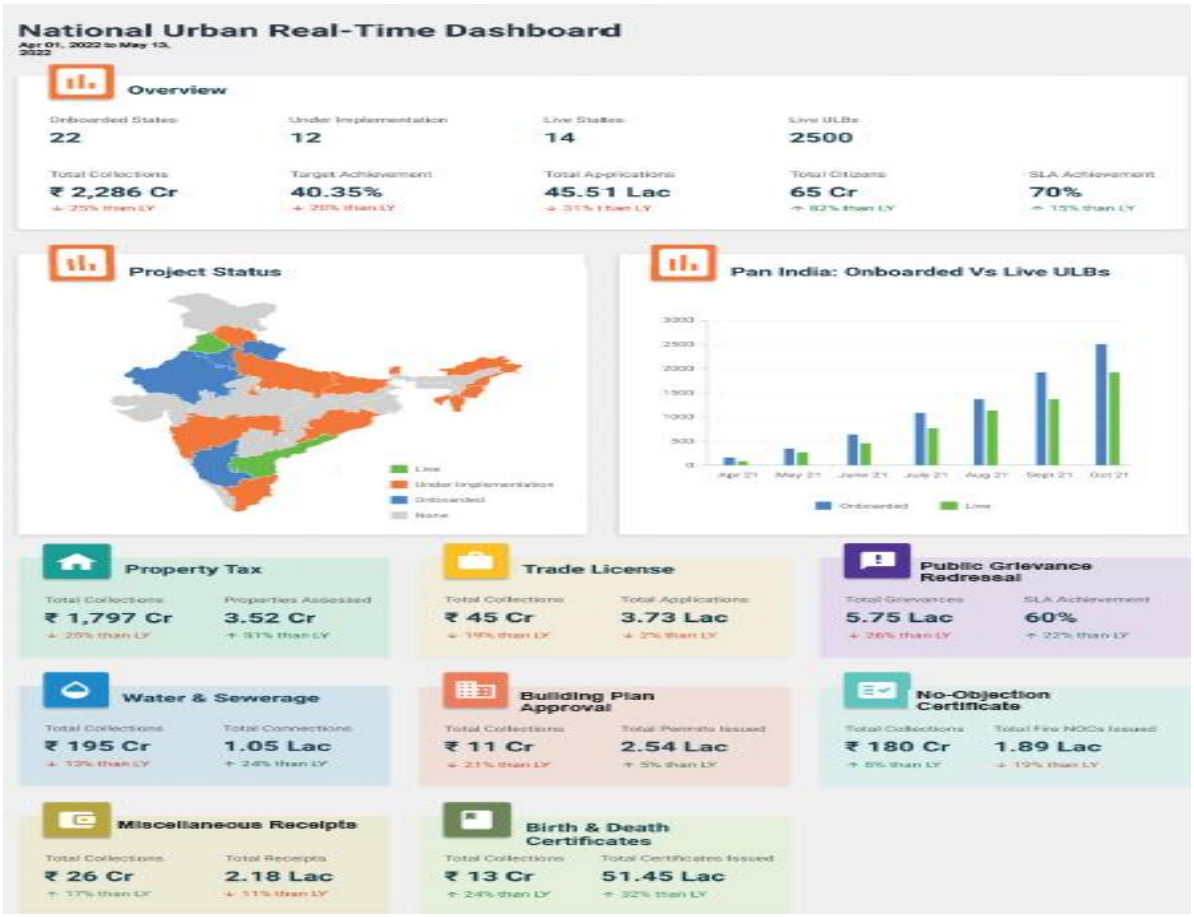

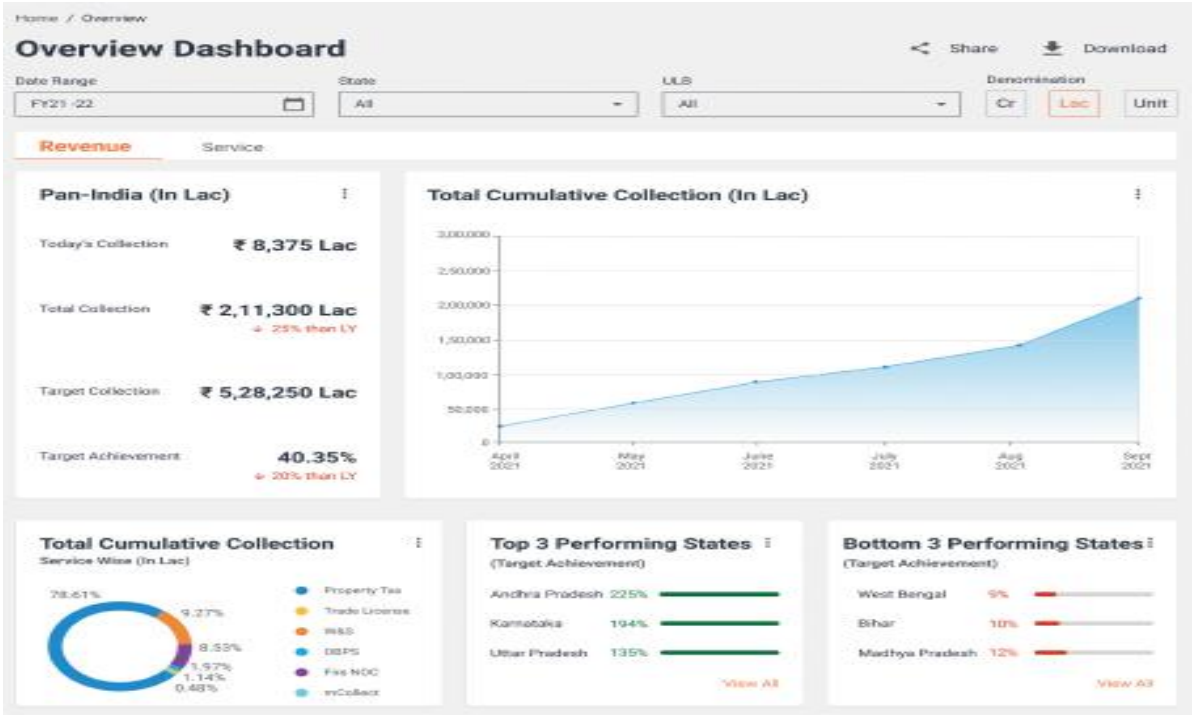

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० का वित्तीय प्रावधान

स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एस०यू०डी०एम०-यू०पी०) के उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रकार से धनराशि की व्यवस्था की जायेगी :-

(1) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत एन०यू०डी०एम० के प्रारम्भिक क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों, जनवरी 2023 के अनुसार क्रमश: वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार से प्राप्त किये जाने वाले रू0 12.50 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 25.00 करोड़ से SUDM-UP का वित्त पोषण किया जायेगा।

(2) अमृत 2.0 के रिफॉर्म एजेंडा यथा- संपत्ति कर, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान लाईसेंस, स्वास्थ्य लाईसेंस, शिकायत निवारण, जल, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट, स्ट्रीट लाईट्स एवं जल निकासी सेवाओं को SUDM-UP के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने हेतु अमृत 2.0 के उपयुक्त एवं संगत मद से भी वहन किया जा सकेगा।

(3) नगरीय निकायों में उपलब्ध करायी गवर्नेन्स जाने वाली नागरिक आधारित एकीकृत आनलाइन सेवाओं, अनापत्तियों आदि के सापेक्ष प्राप्त होने वाले यूजर चार्जेज़ की आय के माध्यम से ।

(4) एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमानुसार कारपोरेट सोशल रस्पान्सिबिलिटी (CSR Fund) से प्राप्त धनराशि का उपयोग भी किया जा सकता है।

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के स्टेकहोल्डर्स के लिए लाभ

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के निम्नलिखित लाभ अर्बन ई-गवर्नेंस सुविधा डिलीवरी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, प्रदाताओं/निकायों को अच्छा प्रदर्शन करने और अपने परिणामों में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है।

➢ लीडर्स के लिए लाभ

- डेटा आधारित उपयुक्त एवं ससमय निर्णय लेना।
- रीयल टाइम मॉनिटरिंग और फीडबैक के साथ ऑनलाइन सुविधा डिलीवरी में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना।
- मूल्यांकन और बेंचमार्किंग के लिए सूचना एकत्र करने के लिए समय की बचत।

➢ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लाभ

- शासन के सभी स्तरों पर कार्य प्रवाह और प्रक्रियाओं पर रीयल टाइम मॉनिटरिंग और नियंत्रण।
- डेटा आधारित उपयुक्त निर्णय लेना जो शासन में प्रभावकारिता की सुविधा प्रदान करते हैं।
- उपयोगिता के अनुसार UPYOG प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज करने की सुविधा।
- समय, प्रयास और वित्तीय व्यय की बचत।

➢ विभागीय / निकाय अधिकारियों के लिए लाभ

- प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति में कमी।
- कार्य में सुगमता एवं सरलता।
- प्रक्रियाओं के स्व-चालन द्वारा त्रुटियों में कमी।
- उत्पादकता और प्रभावकारिता में वृद्धि।
- आवश्यक सेवाओं में लगने वाले समय में बचत।
- प्लेटफार्म के माध्यम से ई-गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन को सरल और सक्षम बनाता है।

- **उद्योग के लिए लाभ**

  - विश्लेषण करने और प्रभावी समाधानों को सक्षम करने के लिए विस्तृत, सटीक और रीयल टाइम डाटा प्राप्त करना।
  - शहरों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ नए उत्पाद बनाने के लिए उच्च व्यावसायिक अवसर उत्पन्न करना।

- **नागरिक के लिए लाभ**

  - भीड़ भरे सरकारी कार्यालयों एवं कठिन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय और प्रयास दोनों की बचत।
  - शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों तक आसान पहुँच।
  - काम करने के लिए एक सरल, उपयोगी और पारदर्शी प्रणाली।

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० के सिद्धांत

- अंतर-संचालित
- नागरिक केंद्रित
- न्यूनतर
- सहयोगात्मक
- समावेशी
- सुरक्षित

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० का रोल-आउट

एस०यू०डी०एम०-यू०पी० का रोल-आउट प्रदेश की निकायों में चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाना है : -

- प्रथम चरण में प्रदेश के 17 नगर निगमों, जनपद-मुख्यालय की नगर पालिकाओं / नगर पंचायतों में।

- द्वितीय चरण में प्रदेश की समस्त निकायों में।

- आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं जनशक्ति की व्यवस्था निकायों में कार्यरत विभिन्न योजनाओं / मिशन्स में उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर / जनशक्ति अथवा स्वयं के संसाधनों से किया जाना।

- आवश्यकतानुसार, आउट-सोर्स / कांट्रैक्ट के माध्यम से जन-शक्ति की व्यवस्था किया जाना।

- म्यूनिसिपल सेवाओं के क्रियान्वन हेतु कार्यरत विभागीय इमपैनल्ड संस्था एन०आई०सी० द्वारा तैयार डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-नगरसेवा के संचालन हेतु अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन करना।